आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 01.07.2025 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- **रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा के मूल किराये में वृद्धि लागू की।**
- **पौड़ी जिले में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन।**
- **प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश से आज थोड़ी राहत मिली। विभिन्न क्षेत्रों में बाधित सड़कों से मलबा हटाने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है।**
- **मानसून के दौरान संभावित आपदाओं को देखते हुए चंपावत जिला प्र□ासन श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क। निर्माण स्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों को सुरक्षित कैंपों में तुरंत शिफ्ट करने के निर्देश।**

रेल किराया बदलाव

रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर–ए.सी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया एक पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में दो पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रेल किराए को युक्ति संगत बनाना और यात्री सेवाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना है। एक रिपोर्ट–

जीएसटी

माल और सेवा कर– जीएसटी लागू किये जाने की आज आठवीं वर्षगांठ है। जीएसटी लागू किया जाना देश के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। इससे कर व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है और व्यापार अनुकूल माहौल सृजित हुआ है। जीएसटी से कराधान में पारदर्शिता, कुशलता और स्थिरता आई है। विभिन्न करों और शुल्कों को एकसाथ मिलाने से कर संरचना सरल हुई है, जिससे अनुपालन भार कम हुआ है और व्यापार सुगमता बढ़ी है।

मानव वन्यजीव संघर्ष

पौड़ी जिले में बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि पौड़ी जिला अति संवेदनशील श्रेणी में है, जहां वन्यजीव हमलों में हर वर्ष औसतन 9 से 10 लोगों की जान जाती है। इसका मुख्य कारण जिले में गुलदार, बाघ, भालू, हाथी, बंदर और सांप जैसे वन्यजीवों की सक्रियता है। बैठक में जिलाधिकारी ने जिले को संवेदनशीलता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित कर कार्ययोजना तैयार करने और ग्राम स्तर पर चेतावनी प्रणाली सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक मृत्यु की जांच के लिए ऑडिट प्रणाली विकसित करने, वन्यजीवों की डीएनए प्रोफाइलिंग, बायो–फेंसिंग और पशु हमलों के आंकड़ों का वर्गीकरण करने पर बल दिया। संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर लाइटें लगाने, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने और वन्यजीव दिखने पर आपदा नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचना देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

पुराने भवन

हल्द्वानी बेस अस्पताल में टाइप– ए के पुराने हो चुके भवनों को अब तोड़ा जाएगा। इसके बाद यहां पर नया भवन तैयार होगा, जिसमें पैथोलॉजी, पीएमएस ऑफिस और टाइप–टू श्रेणी के कमरे बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि हल्द्वानी बेस अस्पताल में जन औषधि केंद्र के सामने टाइप–ए श्रेणी के जर्जर भवनों में कर्मचारी रहते हैं। नियमानुसार अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अस्पताल की ओर से रहने के लिए कमरे नहीं दिए जाते हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अस्पताल का दौरा किया था, तब उन्होंने पीएमएस ऑफिस और पैथोलॉजी को शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। अस्पताल प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। ऐसे में अब जल्द ही यहां पुराने भवन को तोड़ दिया जाएगा। अभी अस्पताल में पैथोलॉजी पुराने भवन में ही है। नया भवन बनने के बाद पहले तल पर पैथोलॉजी लैब शिफ्ट होगी। जबकि दूसरी मंजिल पर पीएमएस ऑफिस और तीसरी मंजिल पर कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे बनाए जाएंगे। पीएमएस डॉ. के.के पांडे के अनुसार ग्रामीण विकास निर्माण निगम से बात हो चुकी है। प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है।

मौसम

प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी बारिश से आज थोड़ी राहत मिली है। बारिश रुकने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बाधित सड़कों से मलबा हटाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। प्रदेश में सौ से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अब भी बाधित हैं। उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं ओजरी में भी भारी मशीनों से कार्य चल रहा है। इसके लिए मशीनरी दिन–रात जुटी हुई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य यमुना घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मौजूद रहकर राहत और पुनर्वासन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को ओजरी से सिलाई बैंड तक पैदल मार्ग से वहां से ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।

इस बीच, राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। शासन और प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, देहरादून और बागेश्वर जिलों में कहीं–कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं–कहीं गर्जन के साथ तीव्र दौर की बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

श्रमिक सुरक्षा

मानसून के दौरान संभावित आपदाओं को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी निर्माण स्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों को सुरक्षित कैंपों में तुरंत शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी संस्थाओं से अपने–अपने परियोजना स्थलों की समीक्षा कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और श्रमिकों आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता से करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस बीच, जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए वर्षाकाल में संवेदनशील क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी महिलाओं की पहचान कर

उन्हें प्रसव तिथि से एक सप्ताह पूर्व नजदीकी संस्थागत सुविधा में ठहराया जाए। आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम के जरिये निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी गर्भवती महिला को समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी और दोषी अधिकारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व विभागीय नियमों के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

ढाबा संचालक निर्देश

आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न करने के उद्देश्य से हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने यात्रा मार्ग के होटल और ढाबा संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मंगलौर क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष शांति कुमार द्वारा पुलिस टीम गठित कर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत होटल व ढाबा मालिकों नोटिस दिए गए। इनमें निर्देश दिया गया है कि होटल और ढाबों पर स्पष्ट रेट लिस्ट चस्पा करने, मांस, मछली और मदिरा के सेवन पर रोक लगाने के साथ ही संचालक के नाम का स्पष्ट साइन बोर्ड लगाया जाए। वहीं ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्कैनर की सुविधा के साथ ही होटल–ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन अवश्य कराने को भी कहा गया है।